

आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 06.11.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :-

- राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित; तीन दिन के सत्र की कुल अवधि 20 घंटे 23 मिनट रही।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और निकायों में कार्यरत नियमित राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने की मंजूरी दी।
- प्रदेश में इस वर्ष धान की अधिक पैदावार के चलते राज्य सरकार ने केंद्र से धान खरीद का लक्ष्य दो लाख मीट्रिक टन और बढ़ाने का अनुरोध किया।
- **और,** दून विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासियों से राज्य के विकास अभियान में भागीदार बनने का आह्वान किया।

विधानसभा विप्लव सत्र स्थगित

उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

सोमवार से शुरू हुए इस सत्र की कुल अवधि 20 घंटे 23 मिनट रही। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सदन को संबोधित किया था।

इस विशेष सत्र में राज्य के पिछले 25 वर्षों के विकास कार्यों और आगामी 25 वर्षों के विकास रोडमैप पर चर्चा की गई।

विधानसभा कार्यवाही

उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्य के भविष्य और विकास को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच गहन चर्चा हुई। मूल निवास, अतिक्रमण और अवैध कब्जों जैसे मुद्दों पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली।

सदन में रानीखेत विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल ने अपनी बात कुमाऊं की बोली में शुरू की, लेकिन अनुवादक न होने के कारण उन्हें हिन्दी में बोलने का सुझाव दिया गया। यह पहली बार था जब विधानसभा में किसी विधायक ने कुमाऊं की बोली में अपनी बात रखने की कोशिश की।

सत्र में देहरादून कैट विधायक सविता कपूर, पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, बागेश्वर विधायक, अनुपमा रावत और आदेश चौहान सहित कई सदस्यों ने अपने विचार रखे।

चर्चा के दौरान देहरादून के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार को मूल निवास लागू करने से परहेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां स्थाई निवास को प्राथमिकता दी जा रही है। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अतिक्रमण और अवैध कब्जों को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि अवैध कब्जे हटाए जाएं, लेकिन वैध कब्जों को मान्यता मिले।

सत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने, सटीक नीतियों को धरातल पर उतारने और दैवीय आपदाओं के मानकों में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

लैंगिक भेदभाव भून्य करने पर जोर

उत्तराखण्ड विधानसभा के विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने वर्ष 2047 तक समाज में लैंगिक भेदभाव को शून्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं और महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है, इसलिए उनका सशक्तिकरण, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मंत्री रेखा आर्या ने सदन में सात विभागों की उपलब्धियां प्रस्तुत कीं। उन्होंने बताया कि राज्य गठन के बाद से महिला, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आवास, खाद्य आपूर्ति और खेल विभागों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं।

मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। अब एक जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए 54 करोड़ रुपये से अधिक और 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के चार माह के वेतन भुगतान के लिये 57 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

मां नंदा राजजात यात्रा से संबंधित चमोली जिले की सड़कों के सुदृढीकरण के लिए भी 47 करोड़ 75 लाख रुपये और नाबार्ड वित्तपोषित सिंचाई व लोक निर्माण विभाग की 73 परियोजनाओं के लिए 271 करोड़ रुपये की स्वीकृति, मुख्यमंत्री ने दी है।

इसके अलावा, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में विभिन्न सड़क और हेलीपैड निर्माण कार्यों के लिये चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है।

चेहरा प्रामाणीकरण प्रक्रिया

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 25 लाख से अधिक लोगों ने अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए चेहरा प्रामाणीकरण प्रक्रिया अपनाई है। डॉ. सिंह ने यह बात कल नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के शुभारंभ पर कही।

धान खरीद लक्ष्य बढ़ोतरी अनुरोध

उत्तराखण्ड में इस वर्ष धान की बंपर पैदावार के चलते राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल राज्य के लिए साढ़े सात लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अब तक लगभग पांच लाख मीट्रिक टन धान की खरीद पूरी हो चुकी है और करीब दो लाख सत्तर हजार किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ले चुके हैं। राज्यभर में 750 खरीद केंद्रों पर धान की खरीदी जारी है।

श्रीमती आर्या ने बताया कि उधमसिंह नगर में इस बार प्रति हेक्टेयर धान की पैदावार सामान्य मानक से काफी अधिक रही है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद केंद्र से लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया। इसके तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव ने केंद्र के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को पत्र भेजकर राज्य का धान खरीद लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन और बढ़ाने का अनुरोध किया है।

प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन— मुख्यमंत्री संबोधन

दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी देवभूमि के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी जहां भी रहते हैं, अपने साथ उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और मातृभूमि की महक लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासियों से राज्य के विकास अभियान में भागीदार बनने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड “विकास भी, विरासत भी” के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि “एक जनपद दो उत्पाद”, “स्टेट मिलेट मिशन”, “वेड इन उत्तराखंड” और “सौर स्वरोजगार योजना” जैसी योजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का लक्ष्य स्वर्ण जयंती वर्ष तक ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां हर युवा को रोजगार मिले, पलायन रुके और प्रवासियों की सम्मानजनक वापसी हो।

प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन—चर्चा

प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के पहले सत्र में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण पर गहन चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान सुझाव दिया गया कि जीडीपी तय करते समय पारिस्थितिकी प्रगति को भी एक महत्वपूर्ण पैमाने के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

सम्मेलन के दूसरे सत्र में संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विमर्श हुआ, जिसमें नारी शक्ति केंद्र में रही। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों ने राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है।

सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखंडियों ने राज्य के विकास के लिए अपने सुझाव दिए और संभावित योगदान पर चर्चा की।

स्पर्ध हिमालय महोत्सव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में साहित्य और साहित्यकारों के सम्मान व प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने देहरादून के थानो स्थित लेखक गांव में आयोजित स्पर्ध हिमालय महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने की पहल की है। उन्होंने बताया कि विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए साहित्यकारों को वित्तीय सहायता एवं अनुदान प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार साहित्यकारों को साहित्य भूषण और लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित कर रही है, जिसके अंतर्गत पाँच-पाँच लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाती है।

गौरतलब है कि महोत्सव के तीसरे दिन योग, आध्यात्म, नाड़ी विज्ञान और पर्यटन पर विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिनमें विशेषज्ञों ने योग और नाड़ी विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कीं।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर—

राज्य स्थापना के रजत उत्सव वर्ष पर आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के तीन दिवसीय विशेष सत्र के समापन की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

अमर उजाला ने संसदीय कार्यमंत्री के हवाले से लिखा है— दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यों का विशेष मॉडल बनेगा।

नवोदय टाइम्स लिखता है—श्रेष्ठता के संकल्प संग विशेष सत्र स्थगित।

राष्ट्रीय सहारा लिखता है विशेष सत्र में चर्चा के दौरान स्थाई राजधानी को लेकर सियासत। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने लिखता है— क्षेत्रीय जरूरत के अनुसार तय होंगे विकास के मानक।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सार्वजनिक उपक्रमों और निगम कार्मिकों के डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी देने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

दैनिक जागरण लिखता है—सार्वजनिक उपक्रमों और निगम कार्मिकों के डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी। इसी खबर पर नवोदय टाइम्स लिखता है—सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों निकायों का महंगाई भत्ता बढ़ा, एक जुलाई से मिलेगा 58 फीसद।

हिंदुस्तान समाचार पत्र ने शीर्षक दिया है— निगम, निकाय, परिषद के कार्मिकों का डीए भी बढ़ेगा।